[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

इकट्ठे हो गये और सब ने वहां हल्ला मचा दिया कि ये आतंकवादी हैं और ये ट्रेन को उड़ाने आए थे । वे बार-बार अपना परिचय-पत्र दिखा रहे थे और उनके परिचय-पत्र फाड़ डाले गए और उनको बेरहमी से मारा गया । वे जख्मी हो गए । उनके साथ जो स्पोर्ट्स किट थे वे सारे छीन लिए गए । कुछ उसमें हाकी के प्लेयर्ज थे । उनकी हाकी स्टिक्स छीन कर उसी हाकी स्टिक्स से मार कर उनको एकदम जख्मी कर दिया गया ।

महोदय, मैंने यह खबर सुनने के बाद मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा था । उस पत्र में यह बात कही थी कि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल 24 दिसम्बर के दिन गुरू गोविन्द सिंह जी के जन्म उत्सव पर पटना साहिब जो कि उनका जन्म-स्थान है और हरेक बिहारी गर्व से कहता है कि गुरु गोविन्द सिंह जो सिखों के दसवें गुरू हैं, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की है उनका जन्म पटना में हुआ है, उस धरती पर खड़े होकर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आज के दिन के बाद मैं देखूंगा कि ये माइनारिटी में रहते हुए सिख कभी भी अपने आपको माइनारिटी में फील नहीं करें और यह फील करें कि वे सुरक्षित जगह में रहते हैं । अगर ऐसी ही रक्षा लालू प्रसाद यादव सिखों को देने जा रहे हैं तो सिखों को तो शायद सोचना पड़ेगा कि बिहार उनके लिए सुरक्षित है या नहीं, जहां सरेआम जबकि एक पुलिस पर्सनल अपना आई कार्ड दिखाकर भी पुलिस से प्रोटेक्शन नहीं ले सकता है तो साधारण आदमी जब अपना परिचय-पत्र देगा तो उसको कहां से संरक्षण मिलेगा ?

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह मांग करूंगा कि अब तक बताया जाए कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं ? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ जबकि वहां सूचना दी गई, एफ.आई.आर. फाईल किया गया। कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके साथ क्योंकि जिस इलाके से ट्रेन गुजरती है वहां पर ला एंड आर्डर की प्राब्लम जो भी होती है वह राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी थी और मैंने इस पत्र के साथ-साथ यह भी लिखा था कि 14 फरवरी से यह खेल शुरू हो रहे हैं, सारे खिलाड़ी वहां पर उपस्थित हैं, कम से कम उनसे मिलकर बिहार सरकार का कोई आफिसर उनसे मिलकर मआफी मांगे और जाकर बताए कि यह गलत हुआ है इस पर आवश्यक कार्यवाही होगी। पर कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई भी बिहार का आफिसर न उनसे मिला और न उनसे कोई बात-चीत की है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहीं पर पता लगता है कि गुरू गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर खड़े होकर लालू प्रसाद यादव, मुख्य मंत्री, बिहार ने जो बातें कहीं थीं उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है और यह बड़ी शर्मनाक बात है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : यह जो बक्सर में घटना घटी है यह बहुत दुखद घटना है और शर्मनाक घटना है, लेकिन क्या यह घटना बिहार सरकार के आदेश से हुई थी ? अहलुवालिया जी क्या कहना चाहते हैं ?

THE VICE CHAIRMAN <DR. NAGEN SAIKIA): No, he need not reply to the question.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

श्री विश्वासराव राम राव पाटिल (महाराष्ट्र) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे मोशन मूव करने का जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सहर्ष गौरव का अनुभव करते हुए मैं यह धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

That an Address be presented to the President In the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased *to* deliver to both Houses of Parliament assembled together on tha21st February, 1991."

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश की एकता और अखंडता को गंभीर खतरा बताते हुए राष्ट्र को सांप्रदायिक और विघटनकारी तत्वों से सचेत रहने की बात कही है। देश की आर्थिक स्थिति भयानक है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उनमें खाड़ी संकट, मुद्रास्फीति बढ़ना, भुगतान शेष की प्रतिकूल स्थिति, अंतराष्ट्रीय संबंधो के ढांचे में गहन परिवर्तन, आंतरिक कलह देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में हिंसा एवं असम में "उल्फा" की गतिविधियों में वृद्धि का विशेषकर उल्लेख है।

महोदय, पंजाब की जो आज की स्थिति है, वह पहले की स्थिति से बहुत भयानक है। इसलिए राष्ट्रपति जी ने यह सही मांग की है कि देश को वर्तमान संकट से उबारने के लिए भारत के लोग एकजुट होकर आएं और समृद्धि और प्रगति के पथ पर जाएं। इसके लिए राष्ट्रपति जी ने जो आव्हान किया है, इस पर सारे देशवासियों को ध्यान देना चाहिए। यह बहुत अच्छा आव्हान है। पिछले साल से कानून और व्यवस्था की समग्र स्थिति में जो गिरावट आयी है, जम्मू-काश्मीर और पंजाब में जो हिंसा जारी है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी ने जो दिशा दी है, उस पर सरकार चल रही है। पंजाब की स्थिति का राजनीतिक हल निकालने की आज आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने कई पहल की हैं। उसमें राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के अलावा सरकार ने उग्रवादियों के साथ बातचीत करने का जो प्रस्ताव है तथा उन्हें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक कार्यों में लगाने का जो विचार है, यह पंजाब समस्या के हल का एक नया पहलू है। जम्मू-काश्मीर में अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्व सीमा पार से हथियार और प्रोत्साहन पाकर तोड़फोड़ की गतिविधियों में लगे हुए हैं, इस ओर सरकार ने ध्यान दिया है। यह जो सारा हो रहा है, इससे सरकार को आशा है कि अपने पड़ोसी देश के साथ अगर बातचीत से संभव हो तो वह सारी स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगी, यह दिशा अपने भाषण में राष्ट्रपति महोदय ने दी है, उसके लिए हम आभारी हैं।

आसाम में जो विघटनकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई है और उसके कारण वहां राज चलाने और सामान्य लोगों को रहने में कठिनाई पैदा हुई है... इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और उसे "अशांत क्षेत्र" तथा उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया। जैसे ही वहां एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल होगी तो वहां असेम्बली के चुनाव कराने की राष्ट्रपति महोदय ने घोषणा की है।

इसमें तमिलनाडु के बारे में भी सुझाव दिया है। तमिलनाडु राज्य में बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए हैं। इनके अतिरिक्त "लिट्टे" के अनेक लड़ाकू संगठन तमिलनाडु में स्थलों का उपयोग अपने कार्यकलापों के लिए करते रहे, जिससे तमिलनाडु की भी स्थिति बिगड़ती गई और लिट्टे के सदस्य वहां अपनी गतिविधियां तेजी से जारी रखते रहे। .....**(व्यवधान)**...

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu): That is not true. We have all objections for this.

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण

[श्री विश्वासराव रामराव पाटिल]

घटना हो गई, लिट्टे के सदस्य 15 व्यक्तियों को हत्या करके फरार हो गए। . . . (व्यवधान) . . .

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: That is not correct. There is no proof for this. You cannot go on telling like this. It is not true *(Interruptions)*-

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना ही नहीं, वहां के प्रधान और मुख्यमंत्री दोनों को ही मालूम, तीसरे को मालूम नहीं था, लिट्टे के बारे में जो सूचना दी थी, वह सही-सही वर्ड बाई वर्ड ट्रांसफर हो गई . . . (व्यवधान) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Let him have his say. I request the Members to, take thein seats . Let him have his own. say. *(Interruptions).*

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा) यह सच्चाई है सच्चाई। . . . . . (व्यवधान) . . . .

SHRI R. GANESH *alias* MISA R. GANESAN (Tamil Nadu): The then Governor, Shri Barnala, refused to give any report In spite of your compulsions he stood like a rock. Without any report from him you dismissed the DMK Government, (*Interruptions).*

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (Tamil Nadu): You cannot make allegations without any proof. He is making false allegations against our leader, without any. proof, . . .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You will have an opportunity. When your turn comes you can make your points.

SHRI GANESAN *alias* MISA' R. GANESAN; He should not make any such allegations.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: The law and order situation in Tamil Nadu was never bad. It was very good.

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra); What is this? Every time they are getting up and disturbing the House. *(Interruptions).*

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): You can meet the allegations when your turn comes. You can make your points. Your Karunanidhi said that. ;... *(Interruptions)....*

SHRl R. GANESAN *alias* MISA R. GANESAN: You need not tell us.

SHRI M. PALANIYANDi (Tamil Nadu): Tamil Nadu is not his own property. We are also Tamilians.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN. We won't allow him to raise it like that ....*(Interrupptions)....*

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: You are the custodian ....(*Interruptions)* .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA)-. Nothing will go on record.*(Interruptions)....*
This is not the way.' ..'.. *(Interruptions)* ....
Nothing is going on record.
__ *OtpiternuvtiOns)....* Members, I request you not to make any personal comments against other Members. Mr. Patil, please go on.

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : हमारे देश का साम्प्रदायिक सामंजस्य मुख्यतः राम जन्मभूमि—बाबरी मस्जिद विवाद के कारण बिगड़ा है। इस बिगड़ते हुए सामंजस्य को देखते हुए सरकार ने अपनी दिशा स्पष्ट की है और सरकार ने धार्मिक नेताओं और दूसरे लोगों से विचार-विमर्श के माध्यम से इस मसले का समाधान करने के लिए नई पहल की है और कोई स्वीकार्य हल निकालने का दृढ़ संकल्प दोहराया है। सरकार

ने यह संकल्प भी दोहराया है कि सभी धर्मों के लोगों के साथ बिना किसी भेद-भाव के समान व्यवहार किया जाए और सारे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाया जाए।

इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर चिन्ता का विषय बन गई थी और यह जो आर्थिक स्थिति बनी है, वह एक दिन की देन नहीं है, वह कई दिनों से बढ़ती जा रही थी और अनिश्चितता के कारण से भी बढ़ी है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि वित्तीय असंतुलन ने इससे पहले लगातार मुद्रास्फीति को बनाए रखा इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि सारे हिन्दुस्तान के लोग इकट्ठे होकर सरकार के हाथ मजबूत करें तभी हम इसका कोई हल निकाल सकते हैं। इस भयावह स्थिति का सामना करने के लिए जो एक राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है, इसका भी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आदेश दिया है।

खाड़ी संकट के कारण भुगतान शेष की स्थिति और अधिक बिगड़ गई और इसकी तरफ भी राष्ट्रपति जी ने ध्यान दिया है और बताया है कि इसके परिणामस्वरूप 6000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आ पड़ने की आशंका है। लेकिन हमारे यहां जो पैट्रोल के भंडार, आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने जो कुछ कदम उठाए थे, उस वजह से हमारे यहां पैट्रोलियम उत्पाद के भंडार संतोष जनक बने रहे अल्पावधि में भुगतान शेष के दबाव को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में निर्यात संवर्धन, आयात पर नियंत्रण और विदेशी पूंजी का अधिक से अधिक अंतःप्रवाह शामिल है।

इस वर्ष व्यापार की स्थिति के बारे में भी अच्छी तरह से दिशा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दी है और हमारी अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए सक्षम है, यह भी कहा गया है।

राष्ट्रपति जी ने बार-बार यह कहा है और इस अभिभाषण में भी कहा है कि हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति हमारी जनशक्ति है और हम अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में हमारी उपलब्धता ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। देश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अच्छी वर्षा हुई जिससे रबी की फसल अच्छी होने की आशा है और इसको देखते हुए जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का योजना दस्तावेज जो मार्च, 1991 को पूरा होने जा रहा है, उस योजना में आवश्यक बुनियादी ढांचे, विशेष कर ऊर्जा, चालू परियोजनाओं को पूरा करने, सिंचाई, घरेलू स्तर पर खाद्य सामग्री संबंधी सुरक्षा, स्वच्छ पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा और दलितों तथा आदिवासियों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, यह भी कहा गया है। हमारे देश की महलिाओं व बच्चों के लिए जो शिक्षा का प्रबंध करना है उसको भी प्राथमिकता दिये जाने का आश्वासन राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिया गया है। कृषि संबंधी उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग करना, कृषि अनुसंधान कार्य की ओर अधिक व्यवस्थित ध्यान देना, कृषि ऋण प्रणाली को मजबूती प्रदान करना और अधिक उत्पादकता और कुशल प्रबंध के माध्यम से पहले से किये गये निवेशों से और अधिक प्रतिफल प्राप्त करने पर विशेष ध्यान केन्द्रीत करना एवं विकास संबंधी प्रशासन को समुचित रूप से विकेन्द्रीकित करना आदि इसमें शामिल किये गये हैं। इससे यही नही बल्कि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि वह कृषि विकास को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। कृषि नीति संकल्प को संसद के इसी सत्र में रखे जाने की आशा भी उसमें है।

नयी कृषि नीति जो आयेगी उससे हमारे देश के किसानों के लिये अधिक अच्छा काम हो जायेगा, यह भी आशा कर सकते हैं और इसमें सभी किसानों

[श्री विश्वासराव रामराव पाटिल]

में आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने वाले सामूहिक प्रयत्नों को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के परिवारों को तथा महिलाओं को भी शामिल करने के लिये भी इसमें क्षेत्र बढ़ाये जाने पर जोर दिया गया है। इसमें स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसम) के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1991-92 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की संख्या दुगुनी कर दी जाये और जवाहर रोजगार योजना भी जारी रखने का फैसला किया गया है। इससे मालूम होता है कि हमारे जो अरबन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं इस रूरल एरियाज में भी अधिक बढ़ोत्तरी और काम मिल जायेगा, ऐसा लगता है।

सरकार ने अपनी औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिये उपाय करने का इसमें आश्वासन दिया है कि देश भर में नयी विकास केन्द्र योजना कार्यान्वित करने का निर्णय सरकार ने किया है, यह भी इसमें कहा गया है। इसमें एक और औद्योगिक नीति पर एक विवरण भी इसी सत्र मे संसद के समक्ष रखे जाने का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि जो औद्योगिक नीति पिछली सरकार ने दी थी उसमें तो सारे के सारे जो बड़े मल्टीनेशनल्स हैं उनके लिये बढ़ावा दे दिया था और उस वजह से हमारे जो उद्योग हैं उनके लिये कुछ अच्छा नहीं किया था। इसलिये नयी औद्योगिक नीति बनाने की बात इसमें दोहरायी गयी है। एक नया विवरण देने से यहां औद्योगिक नीति से रोजगार बढ़ सकेंगे।

सरकार का यह प्रयास होगा कि वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी विकास किये जाने का इसमें आश्वासन दिया है, जिस वजह से संभव है कि वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वजह से जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण लोग हैं उनके विकास का संकल्प लिये जाने का सरकार का इरादा है।

सरकार ने यहां कच्चे तेल, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिये उसे अत्यधिक महत्व देने का वायदा किया है और इसमें यह भी कहा गया है कि हमारे विकास का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जो निरन्तर चलता रहे। ऐसा विकास जो पर्यावरण का विनाश करता है, जीवन के मूलाधार को ही नष्ट करता है तो वह आत्मघाती होता है। इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा के लिये महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। एक दस वर्षीय राष्ट्रीय वनप्रान्त कार्य योजना तैयार की गयी है जिसमें लोगों की सहभागिता पर बल दिया गया है, यह भी उसमें आश्वासन है। भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए भी इसमें आशा की किरण है। इस अभिभाषण में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए सार्थक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है।

इसमें श्रमिकों विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को लागू करने के संबंध में भी विशेष ध्यान देने का वायदा किया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार युवकों के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विशेष ध्यान देगी।

राष्ट्रपति जी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सरकार महिलाओं का संरक्षण करने तथा उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए निर्णायक कार्यवाही करेगी तथा पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा के संबंध में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर अविलंब ध्यान देगी। इससे ऐसा लगता है कि अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने, उनमें शिक्षा का प्रचार करने तथा उनमें व्याप्त सामाजिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा।

राष्ट्रपति जी ने यह स्वीकार किया है कि सरकार यह मानती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकास और सामाजिक न्याय के लिए हमारी रणनीति का एक मुख्य घटक बने। सरकार इस बात पर जोर देगी कि गरीबों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सकारात्मक ढंग से कार्य कर सके और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सतर्क है।

राष्ट्रपति जी ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि बच्चों और माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों का एक प्रमुख अंग रहेगा और जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर को कम करने के लिए अधिक जोर दिया जाएगा ताकि हमारे विकास प्रयत्नों के लाभ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सीमित न रह जाएं।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने शिक्षा और साक्षरता को लोकतंत्र का मूलमंत्र बताया है और यह कहा है कि लोगों में फैली निरक्षरता और शिक्षा का निम्न स्तर कमजोर वर्गों के उत्थान और एक अधिक न्यायसंगत सामाजिक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में मुख्य रूप से बाधक हैं। अतः उन्होंने निरक्षरता को दूर करने पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि सरकार निरक्षरता-उन्मूलन के लिए एक नया कार्यक्रम शुरु करेगी और इसके लिए विश्वविद्यालयों, स्कूलों और स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करेगी और प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इसके लिए यह सुझाव दिया जा रहा है कि स्कूलों, में, कालेजों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई का एक महीना कम करके लगातार 4 महीने तक सारे देश में उनके द्वारा निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का काम किया जाए।

हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है उसके बारे में भी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बिल्कुल सही तरीके से कहा है कि हमारा दृष्टिकोण गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों तथा शांति, निरस्त्रीकरण तथा अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के लिए हमारी वचनबद्धता पर अडिग रहेगा।

राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा है कि सरकार विश्व की प्रवत्तियों के अनुरूप हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने तथा क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की बात को उच्च प्राथमिकता देती है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए बंगला देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के साथ मिलकर काम करने की उत्सुकता प्रकट की गई है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह भी इशारा कर दिया गया है कि हम भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के साथ भविष्य में और दोस्ती बढ़ाएंगे।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर में आतंकवादियों को और अलगाववादी गतिविधियों को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने के बावजूद हमने पाकिस्तान के साथ तनाव खत्म करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं।

द्विपक्षीय मामलों के व्यापक क्षेत्र में विचार-विमर्श शुरू करने के लिए पाकिस्तान से बात की जाएगी और शिमला समझौते का पूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता पर भी हमारी सरकार जोर दे रही है, ये सब बातें अभिभाषण में कही गई हैं।

श्रीमन्, ये सभी बातें जो अभिभाषण की दी गई हैं, उसके लिए हम राष्ट्रपति जी के आभारी हैं। मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि जो मैंने प्रस्ताव किया है, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए, उसे

[श्री विश्वासराव रामराव पाटिल]

आप सब स्वीकार करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); Mr. Mohinder Singh Lather will make a speech seconding' the motion.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने साथी विश्वासराव पाटिल जी ने जो प्रस्ताव राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रकट करने का पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, जहां मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बात का गौरव है कि मैं यह फर्ज अदा कर रहा हूं, वहां मुझे खेद भी है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान अपोजिशन ने जो वाक्-आउट किया, वह मुझे अच्छा नहीं लगा । राष्ट्रपति जी सारे देश के प्रतीक हैं और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी सियासत (पालिटिक्स) से ऊपर हैं...

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY; The Tamil Nadu Government was toppled. That is why we boycotted.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : श्रीमन्, यह ऐसी बात है कि जिसे माफ नहीं किया जा सकता है । बहुत अच्छा हो कि दोबारा ऐसी बात न हो । हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने का बहुत समय मिलता है, अपनी बात हम रख सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपना प्वाइंट आफ व्यू रख सकते हैं। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है, मैं समझता हूं कि खास तौर पर मेंबर पार्लियामेंट साहबान को राष्ट्रपति को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पूरी इज्जत देनी चाहिए ताकि दुनिया वालों को पता लगे कि यहां डेमोक्रेसी है, बहुत सभ्यता वाले लोग यहां रहते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि चन्द्रशेखर जी की सरकार ने सारे मसले हल कर दिए, सारी प्राबलम जो देश में थीं उनका साल्यूशन निकल आया, लेकिन कोशिश की गई है । लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं एक बात के लिए कि आम तौर से जब कोई ऐड्रेस होता है, यहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ज्वाइंट हाउसेज में तो उसमें आम तौर पर सरकार की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, सुनहरे ख्वाब लोगों को दिखाए जाते हैं, लेकिन हम दावा करते हैं कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ उसमें उन्होंने देश की आंखें खोलीं, उन्होंने जो असलियत है वह देश के सामने रखी । मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कहा गया है:

"You are meeting at a time of great stress and challenge. The, unity and .integrity of, the country are under severe threat. Communal and fissiparous elements pose a menace to the nation. The economic situation is a difficult one. Inflation and an adverse balance of payments position,, aggravated by the Gulf crisis, are .matters of-grave concern."

उन्होंने सही तस्वीर देश की आप लोगों के सामने रखी है । सरकार की तारीफ करने की बात उन्होंने नहीं की ।

महोदय, एक बात के लिए और मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपील की है, वह पार्टी पोलिटिक्स के नजरिए से नहीं की है, देश के नजरिए से उन्होंने की है ।

"We must set" aside internal differences, and petty squabbles, all that is narrow selfish and divisive and rise as. one people in the-interest of our nation."

इसीलिए राष्ट्रपति जी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं समझता हूं जैसा मैंने अभी कहा चन्द्रशेखर जी सारी प्रोब्लम्स को हल करने में कामयाब बेशक न हुए हों लेकिन मैं

आपको उस सरकार के बारे में बताना चाहता हूं, वह वक्त बताना चाहता हूं जब 13-13, 12-12 साल के बच्चे-बच्चियां गलियों के अंदर मकानों के अंदर, स्कूल और कालिजों के अंदर अपने ऊपर तेल डालकर जल रहे थे.... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : जबर्दस्ती डाला जाता था ।

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY; Are you against the Mandal Commission? (*Interruption*). ....

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : यह आप भी जानते हैं कि उन बच्चों की वजह से कितना गंदा माहौल पैदा हो गया था । जिस ढंग से जिस नियत से मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, लागू करने की कोशिश की गई, उससे सारे देश का वातावरण दूषित कर दिया गया । छोटे-छोटे बच्चे जोकि सियासत (पोलिटिक्स) के बारे में जानते नहीं थे जल मर रहे थे । अपने आप सैंकड़ों बच्चे मरे होंगे। (**व्यवधान**)

SHRI' S- VIDUTHALAI, VIRUMRI (Tamil Nadu); Are you opposing the Mandal Commission?

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : आप सुनने की हिम्मत रखिए । मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मजहब की लड़ाई हो रही थी... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : इसी तरह से हरियाणा में करा दीजिए। (**व्यवधान**)

SHRIMATI JAYANTHI NATARA-JAN (Tamil Nadu): Sir, what is this?

THE . . VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please take your seats. Let him complete his speech. *(Interruption)*. Ram Awadheshji, please take your seat.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : वहां खून बहाया जा रहा था । हमारे देशवासियों का खून बहाया जा रहा था । सारा देश जल रहा था । (**व्यवधान**) इस देश में मजहबी जहर फैल रहा था । मैं समझता हूं अब बहुत हद तक खत्म हुआ । हमारे देश के अंदर दो-तीन कमियां है जिसके बारे में मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं । हमारे देश के अंदर अलग-अलग मजहब हैं । कहने को तो यह बात कही गई है कि

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दुस्तान हमारा ।

लेकिन आज के दिन यह पोजिशन नहीं है । यहां सिर्फ राम की पूजा नहीं होती । आज के दिन पोजिशन यह है कि

मजहब ही यह सिखाता है आपस में
कि हम हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं,

इतना बड़ा हमारा देश है यहां पर मजहब के नाम पर वोट हासिल किए जाते हैं । मैं समझता हूं सारी पार्टियां शामिल हैं इसके अंदर । सिर्फ अपने महदूद दायरे के अंदर, एकमकसद के लिए, वोट हासिल करने के लिए लोगों को एक्सप्लाएट किया जाता है । मजहबी भावना को एक्सप्लाएट किया जाता है । राम-जन्म भूमि का झगड़ा आज का नहीं सैकड़ों साल पुराना है और सैकड़ों सालों से किसी ने नहीं उठाया । कहां मन्दिर था मुझे पता नहीं, कहां मस्जिद थी मुझे नहीं पता । अंग्रेजी राज चला गया, मुसलमानों का राज चला गया । कांग्रेस का राज चला गया । किसी ने भी राम जन्म भूमि का मसला नहीं उठाया । लेकिन अब क्यों राम जन्म भूमि का मसला उठाया गया ? इसका एक मकसद था कि हिन्दू और मुसलमानों के अंदर एक दरार पैदा की जाए । हिन्दुओं का नाम लेकर, राम का नाम लेकर वोट मांगे जाए। यह हमारे देश की हालत हैं । मैं समझता हूं रशिया के अंदर भी बहुत से चर्चेज हैं, गुरुद्वारे हैं, मास्क्स हैं । वहां पर इबादत होती है लेकिन सियासत से कोई दखल नहीं है । मजहब का सियासत से कोई दखल नहीं होना चाहिए । जब तक सरकार मजहब को दखल न देने के लिए कोई कानून सख्ती से नहीं बनाती तब तक इस देश में मजहब का सियासत में दखल

[श्री महेन्द्र सिंह लाठर]

होता रहेगा और यह देश तरक्की नहीं कर सकता। आज मजहब का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां पर सरकार की जमीन है उस पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया जाता है, नक्शा या प्लान कुछ नहीं बनाया जाता और उस पर अपना कब्जा बनाये रखने के लिए वहां पर मस्जिद, गुरुद्वारा या मन्दिर खड़ा कर दिया जाता है ताकि सरकार उस मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारे को न गिरा सके। वह सारी जमीन हड़प कर ली जाती है। अगर मैं राम का नाम मन में लेता हूं, अपने घर में लेता हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं घर बैठकर भी परवरदिगार को याद कर सकता हूं। लेकिन लाउडस्पीकर लगाकर, जोर जोर से सुना कर, ताकि पड़ौसी भी न सो सकें और सारी रात इस किस्म का ढोंग करना, मैं समझता हूं कि मजहब का दुरुपयोग करना है। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चाहे मंदिर हों, मस्जिद हों या गुरुद्वारे हों, उनमें लाउडस्पीकर लगाकर भगवान के नाम पर लोगों के दिमाग खराब करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। धर्म एक प्राइवेट मामला है। यह मेरा विश्वास है कि मैं किसी को मानूं या न मानूं। मैं समझता हूं कि यह मजहब की लानत जब हमारे देश से जाएगी तभी इस देश में शांति आएगी।

दूसरी बात मैं आबादी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा ध्यान इस तरफ बिलकुल भी नहीं है। फैमिली प्लानिंग का हमारा जो प्रोग्राम, हमारी जो पालिसी है, वह जिस ढंग से चल रही है उससे आबादी को रोकने में जो सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। मजहब के नाम पर ऐसी ऐसी बातें उड़ाई जाती हैं जिनको सुनकर ताज्जुब होता है। यह कहा जाता हैं कि मोहमडन्स पर कोई पाबन्दी नहीं है। वे एक बीबी के बजाय चार चार बीवियां रख सकते हैं। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही हैं और हिन्दुओं की आबादी घट रही है। इस तरह का प्रचार चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे इंडोनेशिया और मलेशिया जाने का मौका मिला है। वे मोहमडन कन्ट्रीज हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना ग्रोथ रेट जीरो परसेन्ट कर दिया है। वहां पर मजहब के नाम पर किसी किस्म की कोई पाबन्दी नहीं है। लेकिन हमारे देश में दूसरी बातें फैलाई जाती हैं। हमें इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जब तक आबादी का बढ़ाव खत्म नहीं होगा, जब तक हम फैमिली प्लानिंग के जरिये आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। इस मामले में हर आदमी और औरत की जिम्मेदारी है कि वह इसके महत्व को समझें। एजुकेशन के जरिये और दूसरे प्रचार माध्यमों के जरिये इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाना चाहिए। आजकल तो ऐसा लगता है कि इस बारे में कोई प्रचार नहीं हो रहा है। हमारे यहां पोपुलेशन का ग्रोथ रेट ढाई परसेंट है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही वर्षों में हमारी आबादी डबल हो जाएगी। ऐसी हालत में हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? इस तरफ सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मामला बहुत खराब हो जाएगा।

तीसरी बात कहते हुए मैं चन्द्रशेखर सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गांवों की दुर्दशा की तरफ आवाज उठाई है। सरकार का ध्यान गांवों की तरफ गया है। उन्होंने कहा है कि जो तरक्की शहरों में हो रही है वही तरक्की गांवों में भी होनी चाहिए। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसता है। चौधरी देवीलाल जब गांवों की बात करते हैं तो उनके अखबारों के मुखालिफ लोग यह प्रचार करते हैं कि वे शहरों और देहात में दरार पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह गलत धारणा है। मैं शहर का रहने वाला हूं। जो सुविधाएं मुझे उपलब्ध हैं, जो सुविधायें मेरे बच्चों को उपलब्ध हैं, अगर वही सुविधायें गांव वालों को भी मुहय्या हो जायं तो इसमें क्या बुराई है? आज स्थिति यह है कि गांव और शहर में फर्क बढ़ रहा है। हमारे

देश में 80 फीसदी लोग गांवों में बसते हैं। आज भी देश के अन्दर ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां पर एक ही पांड से डंगर पानी पीते हैं और वहीं से गांव वाले भी पानी पीते हैं। यह बात आपके नोटिस में भी आई होगी। गांवों में बच्चों के पांवों पर जूते भी नहीं होते हैं। मेरे बच्चे कांवेंट स्कूलों में पढ़ें या बम्बई के इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ें और गांवों के बच्चों के पास किताबें भी न हों तो वे शहरों में पढ़ने वाले बच्चों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? चन्द्रशेखर सरकार जब गांवों के किसानों की बात करती है या मजदूरों की बात करती है तो कुछ लोगों को जलन होती है। शहर में रहने वाला आदमी अगर रिफ्रिजेरेटर रख सकता है, टेलीविजन देख सकता है तो गांव के आदमी को ये सुविधायें क्यों न उपलब्ध कराई जायं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर चौधरी देवीलाल गांव की आवाज न उठाते तो इस देश के अन्दर रिवोल्यूशन आ जाता। आप 80 फीसदी लोगों को बहुत दिनों तक दबा कर नहीं रख सकते हैं। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर देश को ऊपर उठाना है, देश की तरक्की करनी है तो देश के 80 फीसदी लोगों को आगे लाना होगा। 20 फीसदी लोगों के तरक्की करने से इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है।

उपसभाध्यक्ष जी, यहां पर बहुत सी बातों की चर्चा हुई। मैं यह भी नहीं कहता हूं कि चन्द्रशेखर जी ने कश्मीर और पंजाब के मसले को हल कर दिया है। लेकिन एक कोशिश हुई है। इस सरकार का कार्यकाल सौ दिन से थोड़ा ज्यादा है और इस अवधि में एक कोशिश की गई है और नेकनीयती से की गई है कि किसी न किसी तरीके से जो लोग गुमराह हुए हैं, उनसे बातचीत की जाय, उनको बातचीत की मेज पर लाया जाय, कोई न कोई हल उसका निकाला जाय। मैं सिखों को बहुत बहादुर कौम मानता हूं। मैं हरियाणा का हूं जो कि पहले पंजाब का हिस्सा था। यह पंजाब से लगा हुआ है। क्या कभी कोई सोच सकता था कि सिख इस देश के अंदर अपने आप को देश से अलहिदा समझेंगे? वे फौज के अंदर ओहदों में सबसे आगे हैं, खेती करने में सबसे आगे हैं, पुलिस के अंदर सबसे आगे हैं, इंजीनियरिंग में सबसे आगे हैं, मेहनत करने में सबसे आगे हैं, ट्रांसपोर्ट में सब आगे हैं और दूसरे मुल्कों में भी एडवेंचर्स कामों में वे सबसे आगे हैं। लेकिन आज वे अपने आप को इस देश का वासी नहीं समझते हैं, अपने आपको बेबस समझते हैं, लाचार और बेसहारा समझते हैं। यह गलती हमारी है। यह मौका हमने उनको दिया है। अगर ब्लूस्टार न हुआ होता, अगर दिल्ली के अंदर और कानपुर के अंदर उनको न मारा जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार न हुआ होता तो आज हमें यह बात न देखने को नहीं मिलती। हमें अपनी इस गलती को मानना चाहिए। हमें चौराहे पर खड़े होकर यह बात कहनी चाहिये कि गलती हमारी थी। जब तक उनके दिलों के अंदर से यह दर्द नहीं निकलेगा, जब तक वह पीड़ा उनके अंदर रहेगी तब तक हम उनको अपने साथ नहीं मिला पायेंगे। इस दर्द का, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वह नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ दोस्ती की बात करते हैं। दोस्ती बढ़ाना हमारे हित में है। हमें इस ओर पूरी कोशिश करनी चाहिये कि सारे मुल्कों के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हों। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान जो हमारे मुल्क के टुकड़े करना चाहता है, जो टेररिस्टों को हथियार देता है, पैसा देता है, उनको ट्रेड करके यहां भेजता है, उसके खिलाफ हमारी सरकार को जवाबी कार्यवाही करनी चाहिये चाहे इसके लिये हमें कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिये। जब तक हम यह बात नहीं करेंगे, जब तक हम कोई कड़ा कदम नहीं उठायेंगे तब तक हम इस मसले को हल नहीं कर पायेंगे।

अब रही कश्मीर की बात। मुझे यह कहते हुए कोई झिझक नहीं है, यहां बी जे पी० के भाई बैठे होंगे, इसमें खुश और दुख की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह प्राबलम

(श्री महेन्द्र सिंह लाठर)

भी हमारी पैदा की हुई है । अगर कश्मीर के अंदर सीज-फायर न हुआ होता, अगर हमारी फौजें चाहतीं कि दो दिन में सारे कश्मीर को साफ कर देते, पूरे को कंट्रोल कर देते, अगर सीज फायर न हुआ होता तो यह प्राबलम हमारे सर पर न खड़ी होती। मैं 370 के खिलाफ हूं । मेरी राय इस बारे में भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल मिलती है । अकेले कश्मीर की बात नहीं है... (व्यवधान)...मैं जाती विचार आपको बता रहा हूं । मैं आपसे कह रहा हूं... (व्यवधान)...मैं अकेले कश्मीर की बात कर रहा हूं । आप देखिये यह कितने शर्म की बात है कि आज के दिन कोई हिमाचल प्रदेश में जाकर प्रापर्टी नहीं खरीद सकता, कोई दुकान लेकर बिजनेस नहीं कर सकता, कश्मीर में जाकर बिजनेस नहीं कर सकता, वहां पर मकान बनाकर नहीं रह सकता । मुझे यह सुनकर हैरत हुई कि राजस्थान के अंदर भी इसी तरह की पोजीशन बताई जाती है । इस तरह से आज हमनें किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है । हमें अगर इस देश को एक बनाना है तो हमें इस तरह की सारी पाबंदियां खत्म करनी होंगी और जो भाई जहां जाकर रहना चाहते रहे हैं । इंटरस्टेट, रहने और आने-जाने में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिये, उनकी आपस में ब्याह शादियां होनी चाहिये । तमिलनाडु की जब बात आती है कि तमिल वाले खड़े हो जाते हैं । जब असम की बात आती है तो असम वाले खड़े हो जाते । तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा एक देश है, हम एक नेशन हैं ।.... (व्यवधान)...और यह आपने आप को धोखा देना है, सारे देश को धोखा देना है । लोग सब बातें समझते हैं । मैं बात करना चाहता हूं कि इन छोटी छोटी बातों को... (व्यवधान)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBl": It is because of the wrong policies of the Government.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : हमें अगर इस मुल्क को मजबूत बनाना है तो पार्टी पोलिटिक्स और वोट की जो पोलिटिक्स है उससे हमें पर उठना पड़ेगा । जब तमिलनाडु की बात आती है कि तमिल वाले खड़े हो जाते हैं । क्यों ऐसा होता है ? क्या फर्क है तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में ? अगर है तो क्यों है ?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI" States are treated as colonies. That is why this problem.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : यह जो फर्क के द्वार बन गये हैं इनको आपको तोड़ना पड़ेगा ।... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); Ram A,wadheshji, you need not interrupt him. You,don't have the right to reply

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : चन्द्रशेखर जी इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं । इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि कुछ थोड़े से एम०पी० लेकर.... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष जी, चन्द्रशेखर जी ने अपनी लिमिटेशंस के बावजूद, थोड़े से मेंबर साथ होते हुए भी आज तक कोई गलत काम नहीं किया है । उन्होंने देश को मजबूत करने का काम किया । उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की, उनकी सरकार कल जाती है तो आज चली जाए लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए । तमिलनाडु की बात (व्यवधान)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: The Centre should learn how to 'treat the States, how to respect the States. If the Centre fails to respect the States, ultimately the Centre will have to pay the price. Even the British had not treated the ' States like that. Delhi durbar is worse than the British people. *(Interruptions)* . . .

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : अगर भारत की एकता और अखण्डता को खतरा हो तो चाहे 10 राज्यों में गवर्नर का शासन लागू करना पड़े तो करना चाहिये क्योंकि

देश की एकता और अखण्डता के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता है। तमिलनाडु के अन्दर लिट्टे के लोग और आसाम में उल्फा के लोग देश के टुकड़े करना चाहते थे। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती तो देश का नुकसान हो सकता था। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इन सारी बातों को समझ कर अपने देश को उठाने के लिए हमें काम करना चाहिये। आज यहां गल्फ की बात हम करते हैं। गल्फ के अन्दर लड़ाई हुई। उसका असर हम लोगो पर पड़ा। मैं हैरान हूं लड़ाई इतनी दूर हो रही है डीजल और पेट्रोल का जखीरा हमने हिन्दुस्तान में इकट्ठा करना शुरु कर दिया। कहते हैं तेल की कोई दिक्कत नहीं है। जितना तेल पिछली दफा सप्लाई हुआ था उससे ज्यादा तेल सप्लाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी तेल की कमी हो रही है। यह हमारा नेशन है। अगर हम पर हमला हो जाए, हम को लड़ाई करनी पड़े तो हमारे देश का क्या हाल होगा? मैं समझता हूं हमारे देश की बदकिस्मती यह है कि हर आदमी दूसरे को सुधारने की कोशिश करता है कोई अपने अन्दर झाक कर नहीं देखता है कि सुधार तुम्हें भी करना चाहिये। अमरीका ने गल्फ में दादागिरी की। दादागिरी वहां हो रही है। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस है कि वह पर रशिया के कहने के बावजूद और सद्दाम हुसैन ने भी अनकंडीशनल कुवैत से हटने का वायदा कर लिया, उन्होंने आर्डर दिया, फौजें वापिस आ रही हैं लेकिन अमरीका कहता है कि मेरी तसल्ली अभी नहीं हुई है मैं तो अभी और रगड़े मारूंगा। मैंने गल्फ पर बोलते हुए कहा था कि कुवैत को छुड़ाने की अमरीका की मंशा नहीं है, अमरीका की मंशा तो इराक को क्रश करने की है और तेल के ऊपर कब्जा करने की है ताकि सारी दुनियां के लोगों को वह अपनी अंगुली पर नचा सके। यह सच्चाई गल्फ की है। इसलिए जितनी भी बातें हैं, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारी बातों में सरकार से गलती भी होती है और बहुत सारी बातें सही भी होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं जिस रिफ्यूलिंग की बात पर बावेला उठाया गया रिफ्यूलिंग का आर्डर कोई चन्द्रशेखर जी ने नहीं किया और न कोई बाइलेटरल एग्रीमेंट हुआ। यह जो कुछ हो रहा था यह इंटरनेशनल ला के तहत हो रहा था। किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि वी०पी० सिंह गवर्नमेंट ने ओवर फ्लाई करने की इजाजत दी और इस में दोनों बातें इनक्लूड रहती हैं लैंडिंग भी इनक्लूड रहता है और रिफ्यूलिंग भी होती है। लेकिन यह सब छोटी-छोटी बातें हैं। थे समझता हूं जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का सवाल है, उन्होंने कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने टच न किया हो। मैं आपका ध्यान एग्रीकल्चर की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले की सरकारें किसानों के साथ मजाक किया करती थी। एक रुपया क्विंटल उपज का दाम बढ़ता था और 50 रुपये बट्टा खाद का दाम बढ़ता था। लोहे का भाव 500 रुपये क्विंटल बढ़ता था। गेहूं, जीरी और दूसरी फसलों का भाव बढ़ता था एक रुपया प्रति क्विंटल। यह किसानों के साथ मजाक होता था। उनकी रोटी नहीं चलती थी। किसान कर्ज के नीचे दबा पड़ा था। मैं समझता हूं सरकार ने इस दफा जिस का बढ़िया भाव दे कर उनके कर्ज के बोझ को हल्का किया है और कुछ कर्ज माफ भी हुआ है, कुछ उनके पास पैसे ज्यादा आए हैं। मैं फिर दोहराता हूं जब तक किसानों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं होगी, उनकी हालत नहीं सुधरेगी। मुझे चौधरी चरण सिंह की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था मुझे किसी शहर की गलियों में से निकलने दो मैं शहर की गलियों और बाजारो की हालत देख कर बता दूंगा कि यहां के देहातों की हालत क्या है। इसका कारण यह है कि यदि देहात वालों के पास, किसानो के पास पैसा होगा तो वे पैसा ले कर शहर में खर्च करने के लिए जाएंगे। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इस मुल्क में सब से ज्यादा इनकम टैक्स ने लोगों को चोर और बेईमान बनाया है। इस इनकम

[श्री महेंद्र सिह लाठर]

टैक्स की वजह से नम्बर एक और नम्बर दो का झगड़ा रहता है । जब भी बात होती है तो यह कहा जाता है यह आदमी नम्बर एक का है और वह आदमी नम्बर दो का है । सब बातें नम्बर एक, नम्बर दो में होती हैं । मंत्री जी, बजट से जो कुल इनकम होती है स्टेट को उस में से चार परसेंट इनकम टैक्स से आता है । मैं समझता हूं कि आप इन्कम टैक्स खत्म कर दें । कोई बोल्ड डिसिजन इन्कम टैक्स खत्म करने के लें । आज क्या होता है । मेरे पास एक फैक्ट्री हैं । मैं मेहनत करता हूं, जोर लगाता हूं । 8 घंटे के बजाये 16 घंटे काम करता हूं उससे मुझे फालतू इन्कम होती है । वह जो इन्कम मुझे हुई, वह चोरी का पैसा नहीं है । वह चोरी का पैसा तब बना जब मुझे तकलीफ होती है कि वह मेरा कमाया पैसा मुझे सरकार को देना पड़ेगा । उसके लिए मैं रिटर्न फाइल करता हूं, उसको छुपा लेता हूं । उसको छुपाकर खड्डे में डालता हूं या किसी और को देता हूं अथवा सोना ले लेता हूं । वह पैसा सरकुलेशन में नहीं आता है । मैं समझता हूं कि अगर आज हमारी सरकार या कोई सरकार जिसमें हिम्मत है वह नये नये तजुर्बे करे। जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसी तरीके से सरकारें चल रही हैं चाहे किसी की भी सरकार हो । अगर इन्कम टैक्स खत्म किया जाए तो मैं समझता हूं कि सारा पैसा बाहर आ सकता है । वह सारा पैसा इन्वेस्ट होगा, उससे कारखाने और फैक्ट्रियां लगेंगी उसका खर्चा होगा । लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात कोई करने वाला नहीं है। मैं अपने विचारों की यह सिंसियर बात कह रहा हूं । मेरे ख्याल से एक दफा यह सुझाव हमारे साठे साहब ने शायद दिया था । मैं तो पिछली बार भी जब बोला तो इसी बात पर बोला था कि इन्कम टैक्स खत्म करके हमें एक्सपेंडीचर टैक्स आदि लगाने के कोई नये तौर तरीके सोचना चाहिए । आज हमारे देश के अंदर कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो अपनी आमदनी को सही ढंग से बताता हो । आप इन बातों पर गौर कीजिए । अब अगर इनमें कोई सच्चाई है तो इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है । क्यों मैं ज्यादा काम करूंगा ? इन्कम टैक्स देने के लिए । तो उपसभाध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी से फिर रिक्वस्ट करूंगा कि इसके लिए कोई कमेटी बनायी जाए, इसकी स्टडी करायी जाए कि इस ढांचे को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है ताकि इससे सारे देश का भला हो सके ।

एक बात और कहकर अपनी बात पूरी करूंगा । हम तो बदनाम हैं, पोलिटिशियंस को सब गालियां देते हैं । उनको बदनाम किया जाता है लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसर लोग हैं व भी मैं समझता हूं कि किसी तरीके से कम नहीं हैं । इस सरकार में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं । किसी गलत काम का सरकार या कोई पोलिटिशन हुक्म दे दे तो वह चंद मिनटों में हो जाता है और किसी अच्छे कार्य का अगर कोई सरकार फैसला करे, अगर कोई मंत्री महोदय आर्डर कर लें तो उसको लटकाया जाता है, महीनों महीनों, सालों सालों उस पर कारगुजारी होती है । यह बात भी हमें सोचनी पड़ेगी ।

इन्फार्मेशन और ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर यहां बैठे हुए नहीं हैं । मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं । एड्स के ऊपर आपने ज्वाइंट कमेटी बनायी है । एड्स का जो बिल है
It has been referred to a Joint Committee consisting of 30 Members and I was appointed as the Chairman of this Committee. What happened in this Committee. What happened. in saw that it was a very serious and important matter.

सुझाव मंगाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए और मेडिकल कालेजेज से प्रोपोज्ल्स आने चाहिएं, सारे हास्पिटल्स से आने चाहिएं, डाक्टर्स से आने चाहिएं, सबके आने चाहिएं इसके लिए हमने एक कम्यूनिके जारी किया था, सब अखबार वालों को भेजा, रेडियो और टेलीविजन वालों को

भी भेजा। कितनी हैरानी की बात है कि डिपार्टमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं। जो एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी का कम्यूनिके था, एड्स के सीरियस मामले में था

But no publicity was given.

न रेडियो से उसको बोला गया, न टेली विजन पर उसको बोला गया जिसका कि ये प्रचार करना चाहते हैं कि इस बीमारी का पता लगना चाहिए ताकि इसका इलाज हो सके।

Nobody bothered about it.

रोज अनइम्पार्टेंट बातें टी0वी0 और रेडियो पर कही जाती हैं। मैं समझता हूं कि आफिसर्स को सतर्क होना चाहिए और जो पब्लिक मफाद के कार्य हैं जो लोगों के फायदे की चीजें हैं उनको करना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जो गलत काम हो वे फटाफट हो जाते है लेकिन सही कार्य में बाधा डाली जाती है।

मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं और सारे मेम्बर साहिबान का भी धन्यवादी हूं कि मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। मैं दुबारा से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); Now, there are 239 amendments. Most of the amendments, notices for which were received, have already been circulated. Some of the notices for amendments were received late and will be circulated to the Members tonight.

Now, Members have to move their amendments—only to move, not to speak.

SHRI SIKANDER BAKTH (Madhya Pradesh); I move:

15. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namtly;—

"but regret that the Address fails to mention about Government's any specific plan to boost Indian economy by making Indian goods competitive in international market

16. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the firm steps Government propose *to take* to improve the performance of public sector undertakings."

17. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of 'Government to alleviate the sufferings of farmers as a result of diesel shorage in the rural sector."

18. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—<

"but regret that the Address fails to mention about Government's failure to expedite quick disposal of court cases and reduce litigation in different High Courts and the Supreme Court."

19. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of Government to extend comprehensive crop insurance scheme to more crops as demanded by farmers in different States."

20. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about Government's apathy to the recent demolition of temples in Kashmir and the plight of Kashsmiri migrants."

21. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about Government's failure to permit construction of Ram Janambhoomi Temple at Ayodhya."

[Shri Sikander Bakth]

22. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of Government to check the rising unemployment in the country because of less provision of job opportunities per year than the annual requirement."

23. That at the end of the Motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address does not contain any reference to the time-bound firm steps to be taken by Government to curb unabated terrorist violence in Kashmir, Punjab, Assam and other parts of the country."

24. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to give any firm assurance by Gov-vernment to incorporate in law and enforce electoral reforms before the next general elections to curb the menace of money and muscle power elections."

25. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the first steps Government propose to take to restore freedom of press which is threatened by militants in different parts of the country."

26. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about failure of Government to indicate any time-bound programme for universal primary education."

27. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of Government to take steps towards implementation of the Directive Principles regarding protection of Cow and its progeny."

28. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the specific and concrete steps which Government propose to take to curb generation and circulation of black money."

' SHRI MURASOLI MARAN (Tamil . Nadu): I move

41. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that while the Address mentions that policing in sensitive coastal areas left much to be desired and offers of assistance from the Centre were not availed of by the State Government of Tamil Nadu, it conveniently forgets to mention that the Centre had turned down the request of the State Government for providing at least four battalions of the Border Security Force for the said purpose."

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) I move:

42. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain any assurance that the Centre will not misuse powers under Article 356 of the Constitution to dismiss any State Government not to its liking."

43. That at the end of the Motion, *i (he* following be added, namely:—

"But regret that the Address does not mention about the fact that thee Central Government has utilised Article 356 of the Constitution to' Install administration of its own choice as opposed to the choice of the people."

44. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the Sri Lankan Government has a concerted plan to decimate the ethnic Tamil race in Sri Lanka."

45. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about any progress made by the present Government in the investigation of Bofors Scandal."

46. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not contain any assurance that the telephone tapping will be stopped forthwith."

47. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address, while expressing platitudes on inflation, unemployment and agriculture, does not indicate any positive steps in this regard."

48. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any steps to curb the activities of communal and chauv-nistic forces which are posing a threat to secularism."

49. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the specific steps proposed to be taken by Government to solve the Punjab and Kashmir problems."

50. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely:-—

"but regret that the Address does not indicate in clear terms the arbitrary manner in which the democratically elected Government of Tamil Nadu was dismissed and President's Rule imposed there in violation of all rules of democratic cannons and federal spirit as enshrined in the Constitution."

51. That at the end of the Motion, the following be added namely:—

"but regret that the Address fails to assure that the Government will not misuse the provisions of Article 356 of the constitution as is being done in the last several years in our country."

52. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention that in the process of dis-misisng a demomratically elected Government in Tamil Nadu, various constitutional institutions such as offices of the President and Governor have been denigrated and devalued."

a

53. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address deliberately fails to mention the fact that the Governor of Tamil Nadu was arbitrarily transferred and the Governor of Bihar was summarily dismissed because they did not conduct themselves at the bidding of the Centre."

54. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps the Government propose to take against rising cost of essential commodities."

55. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any specific timeframe for arriving at a solution of the Ram Janambhoomi-Babri Masjid dispute."

56. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not indicate about any awareness on the part of the Government that the present Sri Lankan Government threatens all Tamils inhabitated in Jaffna, to evacuate."

57. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the Sri Lankan

[Shri V. Gopalsamy]

Armed Forces, barbaric attacks on innocent civilian Tamil population of Jaffna, bombardment on their localities, temples and churches."

58. That at the end of the Moton, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not reveal the truth behind permitting refuelling facilities to U.S. Air Force transport planes at several airports in India completey deviating from our accepted policy of non-alignment."

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

120. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार अमरीकी सेना के विमानों को ईंधन भरने की अनुमति देकर गुट निरपेक्ष विदेश नीति से विचलित हो गई है।"

121. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम की समस्याओं को ठीक से हल न कर पाने के लिए सरकार की निन्दा नहीं की गई है।"

122. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे के बारे में किसी समयबद्ध समाधान का उल्लेख नहीं किया गया है।"

123. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित न कर पाने और संभाल न पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना नहीं की गई है।"

124. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसे धार्मिक संगठनों का, जो साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए भारी धनराशि जमा कर रहे हैं और इस संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही करने में सरकार की विफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।"

125. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए किन्हीं ठोस प्रस्तावों का उल्लेख नहीं किया गया है।"

126. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सरकार की मंशा प्रदर्शित नहीं की गई है।"

127. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़ी संख्या में लम्बित सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क की चोरी के मामलों और उनके समय-बद्ध निपटारे के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का उल्लेख नहीं किया गया है।"

128. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्न-लिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चालू वर्ष के दौरान देश में हिन्दी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की सरकार की मंशा का उल्लेख नहीं किया गया है।"

129. कि प्रस्ताव के अन्त में निम्न-लिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए किन्हीं विशिष्ट योजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।"

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra); I move:

140. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not contain any assurance to build India into a stable and economically strong nation by pursuing the policies of value-based politics of Gandhiji and Nehru."

MISS SAROJ KHAPARDE: I move:

141. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not make any reference to the fulfilment of the commitment made by the former Minister of Tourism to the effect that the Central Government would share 50 per cent of the cost of the Construction of All-weather Jetty at Elephanta."

142. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention Govt.'s policy to go in for brackish water fisheries in a big way in its seven coastal states, including Maharashtra, in view of the fact that India has lost the first position in the international prawn export market."

143. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to mention about the concrete 3teps taken by Government to settle the long-pend* ing MAHARASHTRA-KARNATAKA BORDER DISPUTE.

144. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address while mentioning about the militants activities in certain parts of the country, does not specify any appropriate device for tackling the situation."

145. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to specify any policy for eradication of poverty and unearthing of black money in the country."

146. That at the *end* of the Motion, the following be *added'* namely:—

"but regret that the Address does not mention about so many vacancies of Judges in the Supreme Court and various High Courts lying unfilled and the urgent need of appointing Judges against those vacancies."

147. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about any specific policy for the Welfare of Child and bonded labour."

148. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not indicate any resolve on the part of the Government to ameliorate the lot of women folk in the country."

149. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the steps proposed to ba

[Miss Saroj Khaparde]

taken to ensure that a female foetus is not destroyed by any, clinical or other means."

150. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention any specific policy of the Government to solve the unemploy-ment problems in the country."

151. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address while making a reference to inflation, does not indicate any positive steps to be taken by the Government in this regard."

152. That at the *end* of ike Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about any positive steps to curb the activities of communal and chauvinistic forces which are posing a threat to secularism."

153. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about any Insurance Scheme for Journalists who have been threatened by militants in different parts of the country."

154. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the stand of Government on the demand by farmers in different States for the extension of comprehensive crop insurance scheme to more crops."

155. That at the *end* the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the sharp decline in the number of foreign tourists into the country and the steps proposed to be taken by Government in this regard,"

SHR I SUKOMAL SEN (West Bengal): I move

156. That at the *end* of the Motion, the following be *added'* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of Government to uphold the policy of Non-alignment and peace in resolving the Gulf crisis and abandoning the role of neutrality by allowing US. Air Force planes to refuel in India."

157. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of Government to play an effective role as the leader of NAM to bring about a peaceful settlement of the Gulf crisis."

158. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the urgent need to include the Right to Work' as a Fundamental Right in the Constitution."

159. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to include 'Right to Education' as a Fundamental Right in the Constitution."

160 That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the grave consequences of Government's seeking loans from IMF with its dangerous condi-tionality that would damags national interests"

161. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the efforts Govern-ment purpose to make to enact laws to ensure workers' participation in management".

162. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not reiterate the commitment to ensure social justice, equality upliftment of Backward Classes and removal of impediment in the way of the proper implementation of the Mandal Commission's recommendations".

163. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention the measures Government purpose to take to constitute the National Women's Commission with adequate powers vested in it".

164. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to effectively curb the atrocities on and killing of the Harijans, SCs, STs and down-trodden people in the country".

165. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:

"but regret that the Address does not mention about the need to reform the judicial system in the country."

166. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to imme diately enact laws for Electrocal re forms".

167. That at the *end* of the Motion, the following be *added*' namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to check ' abnormal rise in prices of essential commodities including edible oils".

163. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need of giving power to the States to levy Consignment Tax to assist them in overcoming the financial crisis".

169. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the growing industrial sickness and closures, rendering thousands of workers unemployed".

170. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the proper rehabilitation of Kashmiri refugees".

171. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to fulfil the long-standing demands for including Nepali, Manipuri languages in the Eighth Schedule of the Constitution".

172. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the need to implement the National Transport Policy Committee's recommendation regarding; gradual phasing out of freight equalisation scheme which has not served the objective of regional development but has instead led to non-optimal location of industries".

173. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the tendency of Government to privatise Public sector enterprises".

174. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation of the Prasar Bharati Act (Broadcasting Corporation of India) regarding autonomy to AIR and Doordarshan".

175. That at the *end* of the Motion, the following be *added*\ namely:—

but regret that the Address does not mention about the reasons why

[Shri Sukomal Sen]

fullfledged Railway and General Budgets cannot be presented in the current Session".

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया (मध्य प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

199. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not condemn supression of democracy in our neighbouring country, Burma".

200. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not condemn the imposition of military dictatorship over democrat!; set up in Surinam."

201. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:

"but regret that the Address does not express its concern over non-utilisation of India's established irrigation potential over 74.28 lakh hectares of land."

202. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of Government to comply with the recommendations contained in the report of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes recently submitted to the Government."

203. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not suggest any alternative in respect of non-availability of Cooking-fuel to the rural and urban poor."

204. That the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:— but regret that the Address does not express any concern over the misappropriation of crores of rupees allocated for. the Jawahar Rojgar Yojna.

205. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:

"but regret that the Address does not mention about the measures to be taken by Government to reduce the disparities in the incomes of rural and urban people."

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): I move:

206. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to condemn in strongest terms the USA and allied forces for going beyond the terms of UN resolution on Kuwait by bombing civilian areas in Iraq during the Gulf War resulting in large scale pelling of innocent men, women and children."

207. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to define the humanitarian aspects involved in the refuelling facilities extended to the war planes of USA in the country during the Gulf War thereby causing great set back to the established non aligned foreign policy."

208. That at the *end at* the Motion, the following be *added,* namely:— ,

"but regret that the Address fails to state the causes the country remaining a mute spectator before and after the commencement of Gulf War."

209. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to state about Government's utter failure in containing the unprecedented rise in prices of almost all the essential commodities in the wake of the Gulf War."

210. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about Government's failure to take stern action against the

hoarders and profiteers who have virtually been looting common men since the Gulf War commenced.'

211. That at the *end* of the Motion, the following he *added,* namely:—

"but regret that the Address does not contain Governments firm commitment to attain self-sufficiency in the production of petroleum products within the country."

212. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not define the various norms and steps to be adopted by Government, particularly by the Ministers and departments in achieving economy by saving petrol and diesel by Government vehicles."

213. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does v not contain an assurance to amend the constitution for granting constitutional status to the Minorities Commission and to make its recommendations binding on the Government."

214. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about Government's intention to open shelter homes with all amenities for the old persons, particularly those neglected by their families and children, in every district and to provide them with financial assistance for their sustenance."

215. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about Government's desire to give monthly financial assistance to millions of widows in the country who are leading a miserable life."

216. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not contain Government's firm commitment to stop the evil practice of child marriages in the country and its desire to raise the age of puberty of girls from the present twelve years to twenty one years by Suitably amending the Indian Penal Code."

217. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to state that despite various laws to contain drug and psychotropic substances' used in the country the drug menace is affecting the precious lives of our youth and that the Government has a desire to fight this menace on a war-footing and making the District Superintendents of Police responsible for drug peddal-ing in their respective areas."

218. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the exploitation of child labour in carpet manufacturing industry, bangle making units, beedi industry, hotels and restraunts, mootr garages and various shops and establishrhents as well as in most of the houses of elites in the society, and Government's resolve to break the shackles of the child labour in the country and give these unfortunate ones proper education and other facilities to become good citizens."

219. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to condemn the child rape cases in the country and affirm Government's resolve to amend the Indian Penal Code for providing death sentence for child rapists in the country."

220. That at the *end* of the Motion,, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to mention about Government's total failure in tackling water and air pollution in the country, particularly in the national capital where the air

[Shri S. S. Ahluwalia]

has become poisonous due to excessive air pollution caused by erring vehicles despite vast powers given to the Government by the Motor Vehicles Act to check the same."

221. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to assure the nation to put a ban on the use of religious sentiments in election campaigns."

222. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to assure the nation that communalism will be wiped out from the country and Government will put a blanket ban on communal organisations and debar candidates belonging to political parties pursuing communal lines from contesting elections to Parliamnet, State Legislatures and local self-government bodies."

223. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about Government's intention to provide compulsory vocational education in the country and open at least one vocational study centre in each District."

224. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to censure some of the political parties and their top leaders for their attempts to divide the nation, on

the communal and caste lines.

225. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to assure the farmers of the country that their crops would be insured against all the natural calamities by Government at its expenses."

226. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about Governments desire to write-off the loans of all the marginal farmers and rural artisans in the country."

227. That at the *end* of the motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Addles.? fails to give an assurance that in future far- mers would continue to get agricul- tural loans without any hindrance from the Banks."

228. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about Government's intention to insure the livestock of farmers at the cost of exchequer."

229. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to assure the farmers that irrigation facilities would be provided by Government to them within a time-frame."

230. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to mention that every village in the country will be connected by pucca roads and provided with electricity, drinking water and means of recreation such as community television sets etc."

231. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about Government's intention to make the economic cri- teria as the only basis for reserva tion for employment in Government jobs and for admission in educational institutions.

232. That at the *end* of the Motion, the the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about Government's intention to reserve appropriate percentage of vacancies in services in

favour of the people living below the poverty line."

233. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about Government's intention to pay adequate compensation to the victims of communal riots and victims of terrorism in the country."

234. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not contain any assurance of the Government to pay adeqcate compensation to the victims of police firing involved in agitations and movements viz., bandhs, picketing, Strikes etc. and observing democratic norms."

235. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about the poorest services being rendered by the nationalised Banks to the consumers thereby defeating the very purpose of their nationalisation."

236. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about fact that more and more nationalised Banks are continuously incurring losses year after

238. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the profiteering being indulged in by the multi-national drug companies and Government's intention to stop the Same with heavy hands."

239. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to give an assurance to contain high prices of life saving drugs."

240. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the rampant corruption prevailing in public dealing departments of Government and the ways to remove corruption from these departments."

241. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to mention about the nexus between ULFA, LITE and terrorists in Punjab and Government's efforts to break this nexus."

242. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to mention about the protection given by some State Government's to the terrorist organisations."

[Shri S. S. Ahluwalia]

of potable water in the State of Bihar wherein almost all the villages, villagers are compelled to fetch water from stagnated ponds and use it for drinking, cooking and washing purposes and as a result suffer from, dreaded deaseases like cholera, hepatitis and ot he gastro-nomical ailments, besides eye and skin ailments, and govt's revolve to provide potable drinking water to every village in the State,"

245. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to state that the State of Bihar is being paid a meagre sum as royalty for mining in the State where Union Government undertakings have been mining and supplying to rest of the country coal, bauxite, Manganese and other precious mineral resources, and that the same will be raised to above twenty five percent."

246. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not make any mention about the devas-tating damages caused by floods every year in the northern parts of

248. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

but regret that the Address does not mention about the Shortage of roads, particularly highways in the State of Bihar and Government's intention to construct a Railway Bridge over the river Ganga in Patna and other interconnecting roads in the State."

249. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about Government's intention to promote food processing industries in the State of Bihar and the tremendous progress made by the State in growing vegetables and fruits creating good potential for such industries in the State."

250. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about Government's resolve to promote fisheries in the State of Bihar."

251. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the miserable living conditions of the Adivasis (Scheduled Tribes) in the State of Bihar

wagon building factory and an ordance factory in the State of Bihar to fulfil the long standing demand of the people of the State."

254. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not containing assurance from Government to promote sugar industry in the State of Bihar and to give clear-ance to the opening of sugar mills in the State."

255. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about Government's resolve to give bank loans on liberal terms to migrant youth from the State of Bihar to the capital of the country and to major cities in other States who come in search of livelihood and are exploited by rickshaw owners and others, So that they may own their rickshaws and earn independently."

256. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not contain Government's assurance to open a Petroleum complex at Barauni industrial area, which falls in the backward district of Begu-sarai in the Bihar State."

257. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not contain Governments assurance to provide irrigation facilities in central and southern parts of the State of Bihar by implementing garland canal scheme and inter-connecting the rivers *viz.,* the Ganga, the Gan-dak, the Mahananda and the Sone in the State."

258. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that- the Address does not contain Government's resolve to fight the dreaded/Kalazaar disease which frequently hits the State of Bihar in the epidemic form."

SHRI ARANGIL SREEDHARAN (Kerala); I move

261. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to mention the proposals for the rehabilitation of Indians who have returned from Gulf countries as a result of Gulf war."

262. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the steps taken by Government to give clearance *to* several projects submitted to it for clearance by State Governments."

263. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the failure of Government to uphold the policy of non-alignment in international relations."

264. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the unrest that is prevalent in certain States because of the failure of the Government to ensure the autonomy of States."

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTNAN; 1 move

265. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention clearly about the arbitrary manner in which the democratically elected Government of Tamil Nadu was dismissed and the President's rule was imposed there, in violation of all cannons of democracy and federal spirit enshrined in the Constitution."

[Shri Pasumpon Tha Kiruttinan]

266. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the concerted plan of Shri Lankan Government to decimate the ethnic Tamil race in Sri Lanka."

267. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the progress made by the present Government in the investigation of Bofors Scandal."

268. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely;

"but regret that the Address does not mention about the arbitrary transfer of Governor of Tamil Nadu and summary dismissal of Governor of Bihar because they did not conduct themselves at the bidding of the Government."

2(69. That at the *end* of the Motion, the following be *addedy* namely;—

"but regret that the Address does not mention about the process of dismissing a democratically elected Government in Tamil Nadu various consitutional institutions such as offices of the President and Governor have been denigrated and devalued."

270. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about any time bound programme or steps Government propose to take to contain the rising cost of essential commodities."

SHRI DINESH GOSWAMl (Assam): I Move

271. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the Government's response to the offer of ULFA for negotiations in spite of the fact that such an assurance was given in Rajya Sabha by the Prime Mi-nister."

272. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the situation has de-teriorated bravely in Assam after the imposition of the President's Rule."

273. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about giving the people of Assam an opportunity to exercise their democratic right for a Government of their own choice.'

274. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention that the prestige of this country has been harmed substantially by red carpet welcome to international arms dealers."

275. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention that there has been gross deviation from the national consensus of our foreign policy in our approach to the problem."

276. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the sorry state of affairs that when peace negotiations are taking place through the efforts of foreign ministers of the non-aligned movement including India, our country do not have a foreign minister."

277. That at the end of the Motion, the following be added, namely:

"but regret that the Address fails to mention that the persons

disqualified under the Anti Defection Act were allowed to continue as ministers and our country was represented in international forums by such persons."

278. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address fails to mention about the steps to be taken by the Government to check the rising prices and hardships to the people."

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): I move:

74. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the fact despite satisfactory level of our stocks of Petroleum products Government has failed to organise effective distribution of diesel as a result of which both agriculture and transport sectors have been badly affected."

75. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the fact that despite our reserves of food stock at satisfactory level Government has badly failed to check the rise in prices of food articles."

76. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the fact that Government has badly failed to check the abnormal rise in prices of edible oils."

77- That at the end of the Motion, the following be *added,* namely:

"but regret that the Address, does not mention about the fact that Government has departed from, the traditional, nationality accepted policy of non-alignment and peace and has badly failed to intervene in the Gulf crisis which has damaged the international prestige of India and the most humiliating act was the refuelling of American military planes going to help the massacre of Iraqi people."

78. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention that India has become the fourth largest international debtor country and the debt servicing ratio has crossed the dangerous point of 30 per cent and Government is still arrange ing for major IMP Loan secretly."

79. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely

"but regret that the Address does not mention that India lis threatened under American super trade law 301 and our economic sovereignty is in jeopardly at in jeopardy at GATT negotiation."

80. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the failure of the minority Government to formulate Eighth Five-Year Plan in time which would prove highly detrimental to the development of the country."

81. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the failure of Government to present the yearly Budget before Parliament when the economic situation is of grave concern and which will further deteriorate".

[Shri N. E. Balaram]

82. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about Government's stand on the Workers Participation in Management Bill and the Bill to amend the Constitution to guarantee jobs to all".

83. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about the need to take determined steps for the implementation of existing Land Reforms, Land Ceiling Acts and Minimum Wages Act for the agricultural workers".

84. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about the need for bringing about a Central legislation on agricultural workers".

85. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the problems arising out of the united European Common Market with whom we are in chronic trade deficit."

86. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not take note of the fact that when the country is facing the threat of disintegration on the question of Centre-State relationship, the Government, instead of implementing the recommendations of Sarkaria Commission, immediately resorted to 'dismissing democratically elected State Governments of Assam and Tamil Nadu and threatening others in such a shameful way that State Governors preferred resignation or dismissal of making false reports calling for dismissal of State Government.

87. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the need for giving power to the States to tax consignment trade in the absence of which most of the Suite Governments are in financial crisis."

88. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the heavy loss to the States like Bihar, West Bengal, Orissa etc. arising out of standardised Railway freights."

89. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the recent massacre of Harijans in Pratap-garh district of U.P."

90. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the recent murder of Harijans by landlords in Tiskohara village under Ma-surhi sub-division of Patna district of Bihar."

91. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the im. plementation of Mandal Commission recommendations."

92. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely;—

"but regret that the Address does not mention about the de mands regarding Jharkhand and Bodo Land.

93. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the Ladakh agitation."

94. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the ever increasing industrial sickness and closures rendering thousands of workers unemployed".

95. That at the end of the Motion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address does not mention about the Kashmiri refugees."

96. That at the end of the Motion, the following be *added,* namely: —

"but regret that the Address does not mention about the demands for inclusion of Nepali and Manipuri languages in the Eighth Schedule of the Constitution." *The questions were proposed.*

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आज जब हम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, तो विश्व के इतिहास में विशेषकर वेस्ट एशिया के क्षेत्र में एक जबरदस्त हलचल पाई जा रही है। चालीस, बयालीस, पैंतालीस साल पहले उपनिवेशवाद के, कोलोनियज्म के जो साए इस क्षेत्र की जनता ने एक-एक करके अपने ऊपर से हटा दिए थे, आज पुनः एक बड़ी ताकत, जिसे हम सुपर पावर के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से कुछ निहित स्वार्थी देशों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुबारा उपनिवेशवाद, नंगा उपनिवेशवाद आज उभर कर सामने आ रहा है। इराक को कुवैत के एनेक्सेशन के सिलसिले में जिस प्रकार से दुनियां के आधुनिकतम हथियारों से लैस 28-29 देशों की सेनाओं ने घेर रखा है और दूसरे महायुद्ध के दौरान जो अमानवीय घटनायें हुई थीं एक-एक करके उनकी पुनः पुनरावृत्ति हो रही है। जिस प्रकार से नागरिकों के ऊपर बमबारी हुई है, जिस प्रकार से वहां के बच्चों और महिलाओं और बूढ़ों और वह लोग जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध से उनका कोई संबंध नहीं था उनको नुकसान पहुंचाया गया है, उन्हें हानि हुई है, उन्हें तकलीफ पहुंची है, वह सब मानव-जाति के लिए एक कलंक बनकर हमारे सामने उभरती है और खेद का विषय है कि दूसरे महायुद्ध के तजुर्बों के बाद जो एक महासंघ दुनियां की मानव जाति को बचाने के लिए और जंग की विभीषिका में दोबारा न पड़ने के लिए बना था संयुक्त राष्ट्र संघ वह भी लकवे का शिकार दिखाई देता है और लुंज-पुंज होकर एक सुपर पावर की गोद में जा कर बैठ गया है, ऐसी स्थिति में भारत के लोगों की, हमारी सरकार की, सब की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं विशेष तौर पर भारत का जो पिछला 40-45 साल का इतिहास है किस प्रकार से हमारे नेतृत्व ने, हमारे नेताओं, ने जब-जब कोलोनिज्म ने, न्यू कोलोनिज्म ने, उपनिवेशवाद ने, नव-उपनिवेशवाद ने, एशिया और अफ्रीका में बसे देशों को अपने मातहत करने की कोशिश की है या उनको किसी न किसी तरीके से आर्थिक रूप से दास बनाने की कोशिश की है, या और मामलात में राजनीतिक तौर पर उनको दबाने की कोशिश की गई हो, गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई में भारत ने हमेशा-हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, अपने फरायज की अंजमादही की है। याद आता है एसे समय पर जब स्वेज कैनाल के ऊपर सन् 1955-56 में जिस प्रकार से जब स्वेज कैनाल के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने कब्जा जमाने की कोशिश की थी और वैस्ट एशिया में एक बार दोबारा उपनिवेशवाद के जो हित हैं उनके संरक्षण के लिए आगे बढ़े थे उस समय जवाहर लाल नेहरू ने आगे बढ़ कर, टीटो, नासर, सुकर्णो, भंडारनायके और दूसरे गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो नेता थे उन सब ने जुट कर एक आवाज से उस साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए कदमों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उस वक्त हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के

[श्री सैयद सिब्ते जी]

चेयरमैन या अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से भारत ने कुछ बुनियादी मुद्दों के ऊपर गुट-निरपेक्ष आंदोलन की बुनियाद रखी थी। मान्यवर, गुट-निरपेक्ष आंदोलन का मतलब केवल यह नहीं था और न आज है कि हम किसी गुट से लगे हुए हैं या नहीं, दुनियां में जो कुछ हो रहा है यदि हमारे यहां हो रहा है तो हम बोलेंगे, लेकिन यदि दुनियां के और किसी कोने में हो रहा है तो हम अपनी आवाज़ नहीं उठायेंगे, यही गुट-निरपेक्षता है, ऐसी बात हमारे गुट-निरपेक्ष आंदोलन के जो मूलभूत सिद्धांत थे उसमें कभी नहीं आई। गुट-निरपेक्षता का आंदोलन इसलिए बनाया गया कि दुनियां कहीं उन कैंपों के करीब न चली जाए जो युद्ध में और अपने मसाइल को युद्ध के जरिए जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं। और एक ताकत बनकर तीसरी दुनियां के लोग उभरे थे। उनके सामने अपने विकास की समस्यायें थीं अपनी गतिशीलता की समस्यायें थीं। इन सबके के साथ-साथ विश्व में एक नया आर्थिक ढांचा कैसे बने एक नयी संपन्नता की लहर अपने पैरों पर खड़े होकर कैसे लायी जाए—यह समस्यायें भी थीं। यह गुट-निरपेक्ष आंदोलन मुख्य रूप से विकास और शांति के लिये उभरा और सारा विश्व जानता है कि दुनिया इस गुट गिरपेक्ष आंदोलन की वजह से कई बार जंग से हम किनारा होते-होते बची और दुनिया में तृतींय विश्व युद्ध नही हुआ। लेकिन विकास और शांति के इस बहुत बड़े आंदोलन को उस वक्त निश्चित रूप से धक्का पहुंचा जब उसी गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक सदस्य देश के ऊपर एक सुपर पावर ने हमला किया। जहां तक मैं समझता हूं कुवैत भी निश्चित रूप से हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है। हम ने कभी भी यह पसन्द नहीं किया कि किसी की सावरिनिटी या सार्वभौमिकता किसी एक देश के जरिये खत्म की जाय। किंतु मान्यवर आप भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार से परिस्थितियां उभरकर आयीं और आज गल्फ में जो हो रहा है, उससे केवल अरब देश ही प्रभावित नहीं हुये बल्कि भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है उस पर भी इसकी परछाइंयां दिखायी देती है। चाहे वह मुद्रास्फीति की बात हो या बैलेंस आफ पैमेंटस की बात हो और चाहे विकास की बात हो, इन सब पर असर पड़ता है। महामहीम राष्ट्रपति जी ने भी इस बात को इंगित किया है कि देश के भंडारन में जो हमारा आयात होगा और उससे जो नुकसान की स्थिति है वह और ज्यादा खराब होगी और परिणामस्वरूप 6 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार हम पर आ पड़ेगा। निश्चित रूप से इस देश की जनता अपनी पूरी शक्ति के साथ इस समस्या का समाधान करने के लिये, इस समस्या का मुकाबला करने के लिये आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से जैसा कि सन् 1973 में हमारे देश के सामने पेट्रोल का संकट आया था और हमने उसका मुकाबला किया था और सन् 1979 में पेट्रोल के महासंकट का सामना किया था। इस तरह जब-जब विपत्तियां आकर पडती हैं, जब-जब राष्ट्र के सामने संकट आकर खडे होते हैं तो हमारे देश के लोग बड़ी निर्भीकता और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुये सन् 1987 में इस देश के अन्दर भंयकर सूखा पडा लेकिन जिस प्रकार से भारत के लोगों ने हमारी पार्टी की सरकार के माध्यम से उस भंयकर सूखे का मुकाबला किया और उस सरकार ने अपनी कार्य नीति से और कार्यकुशलता से उस समय के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के सक्षम नेतृत्व में मुकाबला किया वह सराहनीय है। इस देश का एक भी आदमी अन्न न होने के कारण भूख से नहीं मरा और सन् 1987 के उस महानतम सूखे का जमकर बड़ी निर्भीकता के साथ मुकाबला किया और परिस्थितियां किसी प्रकार से बिगड़ने नहीं दीं। आज की सरकार के ऊपर भी इस बात की जिम्मेदारी आ जाती है कि खाड़ी में जो संकट उठा है उसे सामने रखते हुये उन चुनौतियों

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

और गल्फ-वार की वजह से, जिसका प्रभाव हमारे देश पर भी निश्चित रूप से पड़ा है और आगे भी पड़ेगा, इसलिये असाधारण तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाना होगा। जो हमारी वर्तमान प्रणाली है, उससे सुधार लाना होगा, तभी यह संभव हो पायेगा कि हम लोगों को, जो इस प्रकार की कठिनाई है, उससे बचा पायें।

मान्यवर, आज टेलीविजन पर आप रोज देखें तो किसी न किसी प्रकार से इसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जिसमें जनता से अपील की जाती है कि वह पेट्रोल को बहुत बचाकर खर्च करें ताकि समय की चुनौतियों का मुकाबला यह देश कर सके। एक अच्छी बात है, सीइंग इज दी बिलीविंग क्योंकि जब लोग टी०वी० पर देखते हैं कि पेट्रोल कैसे बचाया जा सकता है और सुझाव सुनते हैं तो निश्चित रूप से इस बात में मदद मिलती है कि किस प्रकार से पेट्रोल को कंजम्पशन बचा सकते हैं। जब हमारा टी.वी. का माध्यम या हमारा रेडियो का मीडिया इस प्रकार के प्रसारण देते है तो निश्चित रूप से... **(व्यवधान)**

चेयरमैन साहब हमको बोलने का मौका दें और व्यवस्था बनाने की कृपा करें। तो मैं अर्ज कर रहा था जब टी०वी०, रेडियो, अखबार और तमाम जो मीडिया हैं, उनके जरिये हम लोगों को इस बात के लिये कन्वीन्स करने का प्रयास करते हैं कि वे पेट्रोल कम खर्च करें तो सरकार का भी यह दायित्व है कि सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं,—चाहे वह आफिसर्स हों, चाहे वह मंत्री हों और चाहे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हैं, वे हों, वे किसी न किसी प्रकार से इस देश की जनता को कन्विन्स करें कि जो कहा जा रहा है उसके वे भी भागीदार हैं, वे कोई अलग चीज नहीं हैं। आज जो हमारे बहुत बड़े-बड़े दौरे होते हैं—राजनीतिक दौरे हों या किसी और प्रकार के दौरे हों, उनको कम करना चाहिये। हमारे राष्ट्र के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी इस प्रकार के खर्चों को कम करने का प्रयास करना चाहिये। शादी ब्याह में अगर कुछ दिनों तक हम न जायें, वैसे तो जायें लेकिन मैरिजिस में, लेकिन दिल्ली में बिहार जायें, दिल्ली से उत्तर प्रदेश जायें, दिल्ली से महाराष्ट्र जायें, केवल किसी अपने मित्र या सगे-संबंधी को खुश करने के लिये।, क्योंकि सार्वजनिक जीवन के अन्दर बलिदान करना पड़ता है, कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। हमारे देश का इतिहास यही बताता है कि जब हमने कांग्रेस के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया तो हमारे नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में उन तमाम कपड़ों का परित्याग किया जो कि विदेश के बने हुये थे और खादी का जो आंदोलन चला तो कभी यह नहीं देखा गया कि गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू जी और दूसरे जो बड़े-बड़े नेता जो थे उन्होंने कभी रेशमी कपड़े पहनकर राष्ट्र का आह्वान किया हो कि वे खादी पहने। क्योंकि खादी पहनने से राष्ट्र के कुटीर उद्योगों को नया जीवन मिलता है और इसी के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना भी थी कि हम सारी दुनिया को दिखा सकें कि हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्दर बने हुये कपड़ों को नहीं पहनेंगे, उस कपड़े को नहीं पहनेंगे जो किसी और मूल्क में बना है, जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है। तो इस प्रकार की भावना थी। तो मैं अनरोध करना चाहूंगा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा और उसके समर्थन में अपनी बात रखते हुये कि हमारी सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यदि देश की जनता से हम बोले, कहें कि वह पट्रोल बचाये तो हमारी भी हर कदम पर यह कोशिश होनी चाहिये कि हम पेट्रोल बचायें और बड़े-बड़े जो जलसे-जलूस हो रहे हैं, उनको भी अवाएड करने की कोशिश करें, तब हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार हम देश की जनता का ज्यादा सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।

निश्चित रूप से बहुत लंबा अभिभाषण है महामहिम राष्ट्रपति जी का और इस लम्बे

का सामना करने के लिये एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाये और सारे देश के लोगों को उस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करे ताकि आगे आने वाला समय बहुत ज्यादा कठिन न हो। निश्चित रूप से आगे आने वाला समय बहुत कठिन है और हमारी मूल्य सूची रोज-ब-रोज बढ़ती चली जा रही है। यह एक ऐसा सिलसिला है जो पिछली सरकारों से जुड़ा हुआ है। पिछली सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बार कहा था कि एक बार चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो वह दोबारा नीचे नहीं आते। प्राइसेस बिल्कुल टूथपस्ट से निकले हुये पेस्ट की तरह है। एक बार टूथपेस्ट से पेस्ट निकल जाय तो वह दोबारा उसके अन्दर नहीं जा सकता। उसी प्रकार प्राइसेस का भी मामला है। मैं समझता हूं कि सरकार अपने प्रिडिसर्स के उस रास्ते पर नहीं चलेगी और सख्त से सख्त कदम उठायेगी मुनाफाखोरों के खिलाफ, जमाखोरों के खिलाफ।

उपसभाध्यक्ष महोदय युद्ध की तरह परिस्थितियां हमारे ऊपर भी प्रभावशाली हो रही हैं और उनका जो लोग फायदा उठा रहे हैं निहित स्वार्थी लोग, चाहे वह किसी भी जगह पर हों किसी भी पोजीशन में हों कितने ही धनाढ्य हों या उन पर राजनीतिक रूप से किसी न किसी का हाथ ही क्यों न हो लेकिन सरकार के हाथ जो हैं वह राष्ट्रीय हित में होने चाहियें और उन पर पड़ने चाहियें। आज जो खासतौर से लोअर, मिडिल क्लास के लोग हैं जो बिल्कुल नीचे दर्जे के तबके के हैं जो फोर्थ क्लास एम्पलाईज हैं जो क्लास थ्री के काम करने वाले लोग हैं हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, निम्न वर्ग के, मध्यम निम्न वर्ग के लोग हैं, यहां तक कि मध्यम वर्ग के लोग भी इन कीमतों के बढ़ने से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने कई बार अपने रेडियो-प्रसारण में, अपने टी०वी० प्रसारण में इस देश के उस वर्ग को चुनौतियां दी हैं, जो चीजों का व्यापार करते हैं। कहीं-कहीं ही नहीं, आज प्रायः देखा जा रहा है कि कुछ लोग इस वक्त और इस समय में मुनाफा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। कई मर्तबा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके खिलाफ सख्त कदम उठायें जायेंगे और इसके लिये वे लोग सरकार को मजबूर न करें कि उनके खिलाफ ऐसे कदम उठाये जायें। मुनाफा कमाना, परिस्थिति से फ़ायदा उठाना, हालात से लाभप्रद होना, यह एक मौलिक प्राकृतिक कमजोरी है, मनुष्य की, मानव की, इंसान की और रेडियो, टी.वी. प्रसारण से, भाषण से चुनौती देने से, आगाह करने से उनकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। इसलिये कीमतों पर काबू पाने के लिये सरकार को अविलंब बहुत सख्त योजनाबद्ध कार्यक्रम करना चाहिये और उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जायें ताकि उन्हें पता चले कि सरकार के आदेशों का अनुपालन न करने से क्या नुकसान उठाये जा सकते हैं। आज तो इस परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है, लेकिन आशा इस बात की जाती है कि भविष्य में कीमतों को रोकने के लिये सरकार कोई कड़ा कदम अवश्य उठायेगी, कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम जरूर चलायेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब देश में महंगाई बढ़ रही और व्यापारी-वर्ग सरकार से देश के शासन से पूर्ण रूप से सहयोग न कर रहा हो तो फिर हमारे पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही रह जाती है। हमें चाहिये कि हम इसको मजबूत बनायें। तेल के लिये, आटे के लिये, दाल के लिये और बहुत सारी जो जरूरियात की चीजें हैं, उन सब चीजों के लिये हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तरीका है, उसे ज्यादा एफेक्टिव बनाना होगा। अभी इसमें इतनी ज्यादा एफेक्टिवनेस नहीं आई है। हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम उसी तरह से हो रहा है, जैसे साधारण परिस्थितियों में हुआ करता था, लेकिन इस वक्त देश असाधारण परिस्थितियों से गुजर रहा है गल्फ-क्राईसेस

अभिभाषण में राष्ट्र की जो मुख्य रूप से समस्यायें हैं, उनका उन्होंने इसमें समावेश करने की कोशिश की हैं और हमारी किसी भी संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत जो भी राष्ट्रपति अपनी सरकार के संबंध में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते है तो सरसरी तौर पर जो उसकी सरकार की उपलब्धियां होती हैं और उसकी सरकार जो आगे करना चाहती है, उसके बारे में विवरण हुआ करता है । जाहिर हैं कि हर बात के ऊपर तफसील से कोई बात करना मुमकिन नहीं होता, संभव नहीं होता और इंगित करने का प्रयास किया जाता है कि इस मुद्दे पर हमारी यह नीति है, इस मुद्दे पर हमारा यह विचार है और इस मुद्दे पर हमारी सरकार यह करना चाहती है । तो पिछले तीन चार महीने की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उस पर कोई चर्चा, जाहिर है कि उसके लिए कोई ठोस बुनियाद नहीं मिल सकती क्योंकि तीन-चार महीने किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिये कोई बहुत असर नहीं हुआ करता । लेकिन वह जो उसका तसव्वुर है, उसका सोचने का ढंग है, उससे उसका जरूर पता चलता है। निश्चित रूप से पिछले तीन-चार महीने में विशेष तौर पर गल्फ वार के सिलसिले में और खास तौर पर रिफ्यूलिंग के ईश्यू पर इस देश के लोग के मन में यह शंका जगी कि शायद हमारी सरकार हमारा जो पुराना रास्ता है गुटनिरपेक्षता का, उस रास्ते से थोडा सा हट रही है । हमें खुशी है कि कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन में इस बात का आश्वासन दिया कि हमारी सरकार और हमारा राष्ट्र किसी भी कीमत पर गुटनिरपेक्षता के रास्ते से नहीं हटेगा । चाहे कुछ भी हो किसी भी गुट के साथ जिसको हम सुपर पावर कहते हैं उससे अपने देश की दोस्ती रखने की बात और है लेकिन उसकी हां में हां मिलाने वाला देश नहीं होगा और निश्चित रूप से अमरीका ने कुछ हद तक इस बात पर सफलता प्राप्त कर ली रिफ्यूलिंग के जरिये कि दुनिया के दूसरे देशों को वह बता सके कि भारत ऐसा देश जो हमेशा गुटनिरपेक्षता की बात करता था, भारत ऐसा देश जो हमेशा तीसरी दुनिया के विकास की बात करता था, भारत ऐसा देश जो हमेशा स्वावलंबन की बात करता था, भारत ऐसा देश जो हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करता था, भारत ऐसा देश जो हमेशा अपने पैरों पर चलना चाहता था, भारत ऐसा देश जिसने अपने असूलों के साथ समझौते की बात कभी नहीं सोची, चाहे उसको पी.एल. 480 को ठुकराना पड़ा हो, चाहे सुपर 301 के बारे में बात कहनी पड़ी हो, आज वह भी ऐसा देश अमरीका के हवाखोरों के अन्दर आकर शामिल हो गया है । खुशी की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय चन्द्रशेखर जी को, प्रधान मंत्री जी को, कि उन्होंने रिफ्यूलिंग के इश्यू पर जो उन्होंने अपनी बात रखी है वह अपनी बात रखने में काफी सक्षम व्यक्ति हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, एक अनुभवी नेता हैं निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात जो रखी उस पर भी गौर करना होगा । लेकिन इस देश के लोग सब कुछ बर्दास्त कर सकते हैं लेकिन यह नहीं बर्दास्त कर सकते कि हम उन ताकतों के पास जाकर खड़े हो जायें, जो सारी दुनिया के अन्दर मौत का व्यापार करते हैं सारी दुनिया के अन्दर असमानता का व्यापार करते हैं सारी दुनिया के अन्दर लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन कभी भी लोकतंत्रीय देश के साथ आकर खड़े नहीं होते हमेशा डिक्टेटर का साथ देते रहे हैं, हमेशा तानाशाहों का साथ देते रहे हैं, कभी भी मजदूरों, दुखियों, दीनों, पिछड़े हुये देशों के साथ आकर वह नहीं खड़े होते । भारत भूखा रह सकता है, भारत नंगा रह सकता है लेकिन भारत यह कभी बर्दास्त नहीं करेगा कि किसी भी इम्पीरियलिस्ट पावर के पास जाकर खडा हो जाय और चन्द्रशेखर जी ने इस बात को साफ किया और निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने भी इसको एक मुद्दा बनाया, क्योंकि हम समझते हैं कि भारत के अन्दर कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

नहीं है बल्कि यह पार्टी उन उद्देश्यों की धरोहर रखने वाली पार्टी न जिसके लिये हमारे नेताओं ने कुर्बानियां की हैं देश को आजाद कराने के लिये और देश की आजादी के बाद देश की अखंडता के लिये, देश की एकता के लिये, देश की सार्वभौमिकता के लिये, देश के गौरव के लिये, देश के आदर के लिये, देश के सम्मान के लिये, देश की प्रतिष्ठा के लिये केवल बातें ही नहीं की हैं बल्कि देश की अखंडता के लिये आजादी के बाद महात्मा गांधी के बाद इंदिरा गांधी ने भी कौम के लिये, इस मुल्क के लिये, इस राष्ट्र के लिये अपनी जान का बलिदान करते हुये यह बताया कि हम किसी चीज से भी समझौता कर सकते हैं लेकिन देश के वकार, देश की इज्जत और देश की जो सार्वभौमिकता है, जो देश की हमारी निर्भरता है, हमारा जो जो आत्मसम्मान है उससे किसी प्रकार का हम समझौता करने के लिये तैयार नहीं हैं।

आज बहुत सारी बातें निश्चित रूप से पिछली सरकार से जुड़ी हुई हैं। आज जो आतंकवाद का माहौल है, आज जो अलगाववाद का माहौल है, आज जो देश में सांप्रदायिक तनाव है वह किन कारणों से हुआ ? अभी मैं उन कारण का नाम लूं तो कुछ लोग खड़े हो जायेंगे लेकिन निश्चित रूप से यह मानकर चलना पड़ेगा कि हमने पिछली सरकार के जमाने में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में उस वक्त की सरकार ने कुछ मानवीय मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया और इसी कारणवश आज देश की यह दशा है कि साप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ चुकी है, जातिवाद के टकराव हो रहे हैं। भारत जो 40-45 साल के अन्दर एक इकाई बनकर खडा हो गया था आज फिर जातिवाद का टकराव का सामना कर रहा हैं, आज फिर सांप्रदायिकता का मुकबला कर रहा है और सन् 1947 की वह कहानी जो आज खत्म हो जानी चाहिये थी, जो आज समाप्त हो जानी चाहिये थी, जिसे लोग आज भूल गये थे, आज हमारी नयी पीढ़ी, नयी कौम, नया हिन्दुस्तान जो सन् 1947 के सांप्रदायिक दंगों के बारे में केवल सुनता चलता आया था, उसने देखा नहीं था उस विभिषिका को, पिछले साल की सरकार जो गुजरी है चाहे वह मंडल आयोग के संबंध में सड़कों पर प्रदर्शन हुये हों और चाहे राम रथ के सिलसिले में सांप्रदायिक उन्माद के कारण तनाव हुआ हों, सांप्रदायिक दंगे हुये हों इस देश की युवा पीढ़ी की मानसिकता के ऊपर भी आघात पहुंचा है और मौलिक रूप से हमारी महान क्षति हुई है। हमारी एकता की क्षति हुई है, हमारी हमारी अखंडता की क्षति हुई है। इस लिये इस नयी सरकार को किसी कीमत पर भी इन बुनियादी बातों पर कोई समझौता नहीं करना चाहिये और भारत का महान उद्देश्य आजादी के बाद बना कि हम इस देश के अन्दर नागरिकता का फैसला जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, समुदाय के नाम पर नहीं करेंगे बल्कि जो भी भारत की धरती पर पैदा हुआ है और भारत की धरती को अपना वतन समझता है, ऐसे हर इंसान को बराबरी का हक है।

जवाहर लाल नेहरू ने आजादी के बाद कहा था कि यह जो हमारे देश के विभिन्न धर्म हैं मजहब हैं वे सब हमारे अपने मजहब हैं। हिन्दू हो या मुसलमान सिख हो या ईसाई जैनी हो या पारसी जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है वह भारत का है और भारत की संपत्ति में, भारत की संपद में भारत की वैल्थ में, भारत के जर्रे-जर्रे में उसको बराबरी का हक है। हिन्दू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे लोग अपनी परम्पराओं के लिहाज से अपने विश्वासों के लिहाज से अपने धर्म का पालन करें अपने धर्म पर चलें लेकिन इन सबके साथ ही साथ हम अपने मादरे-वतन के लिये अपने मुल्क के लिये अपने देश के लिये एक जज्बा रखें कि हम भारतीय है।

आजादी के बाद के 40–42 सालों के इतिहास से आप भली-भांति परिचित हैं। अगर आप इस इतिहास को देखें तो जब-जब मुल्क पर आपत्ति आई है, जब-जब हमारे देश पर विदेशी हमला हुआ है, राष्ट्र एकसूत्र में बंधकर खड़ा हुआ है। राष्ट्रीयता की पहचान रोजमर्रा के कामों से नहीं बल्कि देश पर जब आक्रमण होता है और देश की एकता और अखंडता को जब चुनौती होती है, उस वक्त होती है और इस बात से होती है कि कौन देश की खातिर खून बहा सकता है, कौन देश के लिये अपनी जान दे सकता है, कौन देश के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। ऐसे हालात पर जब हम नजर डालते हैं, इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कश्मीर के अन्दर जब पाकिस्तान की फौजें आजाद कश्मीर के सिलसिले में आगे बढ़ रहीं थीं तो खून अगर किसी का गिरा था तो एक भारतीय का गिरा था। हो सकता है कि उस भारतीय का नाम ब्रिगेडियर उस्मान रहा हो। रण और कच्छ के इलाके में जब पाकिस्तान ने टैंकों का प्रयोग करते हुये हमारे बहादुरों को ललकारा था तो उस वक्त भी एक भारतीय आगे बढ़ा था और हो सकता है कि उसका नाम अब्दुल हमीद रहा हो।

इस प्रकार से हमने देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और हमें उसमें सफलता मिली लेकिन हमें अफसोस है कि कुछ विदेशी ताकतें हमारी इस एकता से खुश नहीं हैं। हमने इस देश के अंदर सैक्युलरिज्म और धर्म-निरपेक्षता का जो तजुर्बा किया है, उससे खुश नहीं हैं, लोकतंत्र का जो तजुर्बा किया उससे खुश नहीं हैं, समानता के रास्ते पर जो हम चलना चाहते हैं और जो हमने प्रगति की है, उससे खुश नहीं हैं। यह समता और समानता का ही रास्ता था, एकता का ही रास्ता था, लोकतंत्र का ही रास्ता था, राष्ट्रीयता और अमन का ही रास्ता था कि वह देश जो आजादी से पहले सारी दुनियां में भूखे, नंगे, प्यासे देश के रूप में जाना जाता था, वही देश जब अंगड़ाई लेता है तो इसी एकता के बल पर दुनियां के उन 10 बड़े देशों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है जो विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक देश माने जाते हैं।

एकता और विकास परस्पर जुड़े हुए हैं। इस देश में विकास संभव नहीं हो सकता था अगर सिख, ईसाई, हिंदु, मुसलमान, सारे के सारे आगे न बढ़ते, एक साथ कारखानों में, खेतों में, खलिहानों में काम न करते। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या यह मुमकिन था कि 200–300 साल तक गुलाम रहने वाला, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसकर जिंदगी गुजारने वाला देश केवल 40 साल के अंदर जब अणु बम का शांतिमय ढंग से तजुर्बा करता है तो दुनियां के 6 बड़े देशों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये चीजें कुछ देशों को अच्छी नहीं लग रही हैं, कुछ बड़े देशों को अच्छी नहीं लग रही हैं, कुछ पड़ोसी देशों को अच्छी नहीं लग रही हैं। देशों की राजनीति होती ही रहती है। लेकिन अफसोस हमें इस बात का होता है कि जब अपने ही देश के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, फिरके के नाम पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। काहे के लिए? सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए? सत्ता में आने के लिए? भारत अगर कमजोर होगा तो आगे आने वाली नस्ल को हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत अगर टूटेगा तो हमें उसके लिए जिम्मेदारी उठानी होगी। इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर जो हमारे मौलिक सिद्धांत हैं, बुनियादी उसूल हैं, उन पर किसी प्रकार से समझौता नहीं करना होगा। धर्म निरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर उन तमाम ताकतों को सोचना होगा कि हम किस रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR NAGEN SAIKIA): Mr. Sibtey Razi, it is nearing six. Will, you complete now or eentinue?

SHRI SYED SIBTEY RAZI: I can continue tomorrow.

SHRI SUKOMAL SEN: We should adjourn at six.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA[1]); You can speak for three minutes more.

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : तो उन ताकतों को जो धार्मिक उन्माद का सहारा लेकर धर्म के जज्बातों का सहारा लेकर इस देश के मौलिक, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि यदि देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फासिज्म आ जाएगा। यदि देश में फासिज्म आ जाएगा तो देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो देश के अंदर हिन्दु मुसलमान की बात मत करो, इस देश के अंदर असंख्य जातियां रहती हैं, इस देश के अंदर मुख्तलिफ भाषायें बोलने वाले, विभिन्न पहनावे पहनने वाले लोग रहते हैं। यह देश कहीं कन्याकुमारी है, कहीं काश्मीर है, कहीं तमिलनाडु है, कहीं आंध्र प्रदेश है, यह देश कहीं गुजरात है, कहीं बंगाल है और हर प्रदेश की अपनी विशेषतायें हैं। यदि हम हिन्दु मुसलमान के इस मसले को फासिज्म के जरिए, धार्मिक उन्माद का सहारा लेकर देश में मंदिर और मसजिद के नाम पर सत्ता में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो

हम जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल
किसे देखकर आप शरमाइएगा ?

तो ऐसी परिस्थितियों में हमें समझदारी का सबूत देना चाहिए। निश्चित रूप से मौजूदा सरकार किन परिस्थितियों में आई, यह तो आप भलीभांति जानते हैं। आज भरसक प्रयास इस बात का किया जा रहा है, बार-बार इस बात को शक्ति देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं चाहती, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है, जनता दल चुनाव चाहता है, दूसरी पार्टियां चुनाव चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव नहीं चाहती। हमारा एक ही सवाल है आपसे इस बारे में कि पिछले चुनाव नवंबर 1989 में हुए थे। हर पार्टी ने अपने मैनिफैस्टो में यह कहा था कि हम स्थाई सरकार देंगे। स्थाई सरकार कितने दिनों के लिए? स्थाई सरकार एक साल के लिए? स्थाई सरकार 6 महीने के लिए? स्थाई सरकार चार साल के लिए या 5 साल के लिए? तो जनमानस के अंदर जाकर चुनाव लड़ते समय इस बात का प्रचार किया गया कि हमें एक बार वोट देंगे तो हम 5 साल के बाद वोट मांगने आयेंगे। आज किस मुंह से किस बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिएं? हमारा देश बड़ी समस्याओं से जूझता हुआ देश है। हमारी आर्थिक समस्यायें हैं। न जाने कितने गांव हैं जहां रोशनी नहीं है। न जाने कितने गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं है। न जाने कितने गांव हैं जहां स्कूल नहीं हैं। न जाने कितने गांव हैं जहां हैल्थ सेंटर नहीं हैं। न जाने कितने करोड़ों लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जिनको अक्षर पढ़ना भी नहीं आता। न जाने कितनी झोपड़ियां हैं जहां खाने की व्यवस्था नहीं है, आज बार-बार चुनाव का नारा लगाने वाले, देश की आर्थिक परिस्थितियों पर आर्थिक दबाव डालने वाले, देश के, लोकतंत्र के हितैषी नहीं हैं

(भाषण समाप्त नहीं हुआ)

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (DR, NAGEN SAIKIA): You can continue your speech tomorrow.

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 26th February, 1991, allotted 4 hours for the "General discussion on the Interim Railway Budget for 1991-92". The Committee recommended that a discussion on Tamil Nadu may be taken *up* **after the** reply to **the**